

## समावेशी शिक्षा Inclusive Education

समावेशी शिक्षा को मुख्यता 3 भाग में रखा गया है –

Physical Disability (शारीरिक, मानसिक विकलांग)

Learning Disability (अधिगम अशक्तता)

Children from : (i) Scheduled caste (अनुसूचित जाति), (ii) Scheduled tribe (अनुसूचित जनजाति), (iii) Economically weaker section, (निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे)

इन तीनों बिन्दुओं में समावेशी शिक्षा को देखा जा सकता है।

समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना या प्रदान करना है इस शिक्षा में सभी बच्चों को सामान्य रूप से शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों से अर्थ : उन में कुछ बच्चे विशिष्ट ( special children ) हो सकते हैं। शारीरिक विकलांग या कोई शारीरिक कमियाँ हो जैसे, सुनाई नहीं देना, चलने में कठिनाई, मानसिक विकलांग या लिखने पढ़ने में कठिनाई महसूस करना, तथा जो अन्य बच्चों से कमजोर हो सकते हैं। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बच्चों की छुपी हुई योग्यता को उभार जाए यह मुख्य उद्देश्य विशिष्ट शिक्षा का है।

आज केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ही बढ़ावा ना दिया जाए बल्कि सभी प्रकार से कमजोर या पिछड़े बच्चों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (Scheduled Cast ) पर उचित ध्यान दिया जाए ताकि वह देश की मुख्य धारा में आकर वे भी अपनी योग्यताओं का विकास करे और देश की उन्नति में योगदान कर सके।

प्रतिभाशाली( Genius) बच्चा जिस को सब कुछ आता हो और वह सब कुछ जल्दी जल्दी सीखता हो।

ऐसे बच्चों के लिए भी कोई अलग स्कूल नहीं होना चाहिए – तो इन सभी बच्चों को हमें एक ही स्कूल में पढ़ना होगा।

शैक्षिक संस्थान को देखना चाहिए समाज में इन सभी बच्चों को एक स्कूल में ही डालना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए की बच्चों पर दबाव दे रहे हो की आप इस तरह सिखें। शिक्षा प्रणाली ( Education system )को बदलना चाहिए या Adjust करना चाहिए की वो विकलांग बच्चों के लिए Special Device दे या Special तरीका सोचे उन्हें सिखाने के लिए और अलग अलग तरीके से सिखाए और उन्हें अलग नहीं समझें Normal बच्चों से ।

नोट – समावेशी शिक्षा का अर्थ लोग यह समझते हैं इसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। पर ऐसा नहीं है वास्तव में समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों तक नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है।

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य ( Aims of Inclusive Education ) :

समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं –

बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता का पाता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना।

विशिष्ट बच्चों को आत्म – निर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना।

लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना।

जागरूकता की भावना का विकास करना

बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास करना आदि।

समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा में दाखिले से वंचित ना रह पाये।

समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए की कोई भी बच्चे को चाहे वह शारीरिक अपंगता से ग्रस्त हो फिर भी शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्हें आंगनबाड़ी और स्कूली शिक्षा से किसी प्रकार से नहीं रोका जाएगा।

समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए कि शारीरिक विकलांगता और मानसिक रूप से अपंग बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को गैर शैक्षिक संस्थाओं को विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे आध्यपकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो।

इस शिक्षा के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाओं का कर्तव्य होता है कि वह यह सुनिश्चित करे की ऐसे बच्चों के लिए जो शाहरो से दूर है उन के लिए छात्रावास का प्रबंध करे।

समावेशी शिक्षा अधिनियम Disability Act 1995 और National Trust Act 1999 मे स्पष्ट किया गया है –

Blindness

Low Vision

Leprosy Cured

Hearing impairment

Locomotor Disability

Mental Retardation

Mental illness

Autism

Cerebral Palsy

Multiple Disabilities

निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा (Poor and Backward Classes Children and their Education)

निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाने के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, और सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है जो निः शुल्क प्रदान की जा रही है, पर निर्धनता के कारण माता – पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। जिस से समावेशी शिक्षा के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों की निः शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है। जिस में निर्धनता की समस्या को देखते हुए स्कूलों में मध्याह्न भोजन स्कीम लागू किया गया है। जिस से माता – पिता उन्हें स्कूल भेजे ना की काम पर।

सामावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं,

जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं-

बालकों के लिए मुफ्त किताबों की व्यवस्था करना।

मुफ्त पोशाकें तथा छात्रावासों का प्रबन्ध करना

सभी स्तरों पर निः शुल्क शिक्षा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे एवं उनकी शिक्षा

औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अलग रखा गया है। पहला जाति के आधार पर विभाजित समाज में सबसे पिछड़ा होने और दूसरे उनके भौगोलिक स्थिति तथा सांस्कृतिक अन्तरों के कारण उच्च समुदाय ने अपने हित के लिए उनका हनन किया।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की शिक्षा के खराब स्तर के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं –

विद्यालय में अनुसूचित जनजाति के बालकों का प्रवेश कम होना

अध्यापक द्वारा उनके शिक्षण के प्रति खराब दृष्टिकोण ।

बौद्धिक क्षेत्र से पिछड़े होना

निर्धनता

इन वर्गों में शिक्षा के महत्व और प्रचार प्रसार का अभाव

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा तथा अन्य अधिकारों से वंचित समुदायों के उथन के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया जिस से उनका समुचित विकास हो सके।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु भारतीय संविधान की धाराओं 15 (4), 45 और 46 में विशेष प्रावधान दिया गया है।